दैनिक जागरण
रविवार, 30 नवंबर 2014 : मार्गशीर्ष शुक्ल 9, 2071

अनुशासन परिष्कार की अग्नि है, जिससे प्रतिभा योग्यता बन जाती है

आतंक का खतरा

खूंखार आतंकी संगठन आइएस के एक आतंकी के मुंबई लौटने के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह की यह चिंता सही जान पड़ती है कि कुछ युवा इस आतंकी संगठन के अतिवाद से प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले में जो स्थिति भारत की है वही करीब-करीब अन्य देशों की भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि इस्लामी देशों के अलावा किस तरह अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के तमाम युवा आइएस से जुड़कर सीरिया और इराक में मार-काट बचा रहे हैं। इस मामले में सबसे आश्चर्यजनक है कि चंद महीने के अंदर यह आतंकी संगठन दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन बन बैठा और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह भी कम आश्चर्यजनक है कि इस संगठन की क्रूर हरकतों और उसके खूनी इरादों से परिचित होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे निपटा जाए? इसमें संदेह है कि केवल हवाई हमलों के जरिये आइएस की कमर तोड़ी जा सकती है। यह संगठन जिस तरह अभी भी अपने कब्जे वाले तेल के कुओं से कच्चा तेल बेचकर मालामाल हो रहा है उससे उसके समक्ष विश्व समुदाय की एक किस्म की लाचारी ही प्रकट हो रही है और शायद यही कारण है कि आइएस आतंकी अपने दुस्साहस का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आइएस के समक्ष अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक मात्र विफलता यह नहीं है कि वह उसके दुस्साहस का दमन नहीं कर पा रहा है। यह संगठन जिस तरह इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया के जरिये दुनिया भर में अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा वह भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से पश्चिमी देशों की विफलता का एक प्रमाण है।

सुरक्षा के मामले में कहीं अधिक चौकसी बरतने वाले पश्चिमी देश यह भी नहीं जान सके कि उनके युवा किस तरह चोरी-छिपे निकलकर सीरिया पहुंच रहे हैं। कम से कम अब तो पश्चिमी देशों को सबक सीखना ही चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें और अधिक चौकसी का परिचय देना होगा। ऐसा ही परिचय भारत को भी देना होगा, क्योंकि भले ही पश्चिमी देशों के मुकाबले आइएस से जुड़ने वाले भारतीय युवाओं की संख्या बहुत कम हो, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस संगठन की विचारधारा युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। इस तरह की विचारधारा से लड़ने के लिए आंतरिक सुरक्षा के तंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर भी पहल करनी होगी। उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते युवा एक ऐसी विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो क्रूरता का पर्याय बन गई है। आइएस के संदर्भ में गृहमंत्री ने जो चिंता जताई है उस पर आंतरिक सुरक्षा के तंत्र से जुड़े सभी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। वैसे भी आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर यह जरूरी है कि हर छोटी-बड़ी चुनौती के लिए हर वक्त तैयार रहा जाए और आइएस ने तो कहीं अधिक गंभीर खतरा उत्पन्न किया है। आइएस के एक आतंकी के मुंबई लौटने के मामले में न केवल गहन छानबीन की आवश्यकता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी कि भारतीय युवा आइएस का हिस्सा न बनने पाएं।

सबक ले सरकार

राज्य में मानव अधिकारों की स्थिति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणी से सरकार को सबक लेना चाहिए। आयोग अध्यक्ष का कहना है कि मानवाधिकार हनन के मामलों में हरियाणा अन्य राज्यों से पीछे नहीं। बात पुलिस उत्पीड़न की हो, सरकारी योजनाओं के लाभ की या दलित अधिकारों की , हर क्षेत्र में अंगुली उठाई जा रही है जो सबसे तेज प्रगति कर रहे राज्य के लिए उचित नहीं। आयोग की विशेष टीम ने तीन दिन चंडीगढ़ में शिकायतें सुनीं जिनके आधार पर निष्कर्ष सामने आया कि मानवाधिकारों की स्थिति पर राज्य में बहुत काम किए जाने की जरूरत है। सरकार को कई स्तरों पर गंभीर मंथन करके ऐसा निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए जो राजकीय विभागों के साथ सामाजिक व्यवस्था के पहलुओं को निरंतर देखे-परखे और समस्या के निदान में कारगर भूमिका निभाए। दलित उत्पीड़न के कई मामले राष्ट्रीय स्तर तक गूंज चुके, लंबी प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई के बाद भी यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता या सरकार व्यवस्था पर उनका विश्वास नहीं जमता तो इसका यही अर्थ होगा कि कहीं न कहीं गंभीर खामी है जो सरकार के संज्ञान में नहीं या फिर वह उसे जानना नहीं चाहती। एक तरह के मामलों की लगातार पुनरावृत्ति होती रहे तो शासन-प्रशासन की कार्यशैली और विवेक पर सवाल उठना लाजिमी है। ऐसे में उसकी किसी दलील या तर्क की स्वीकार्यता नहीं रहती। समाज कल्याण व रोजगार के लिए चलाई गई सरकारी योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव हर स्तर पर देखा जा सकता है। यदि इनका प्रवाह सहज-स्वाभाविक न हो तथा निगरानी पर गंभीरता न दिखाई जाए तो योजनाएं भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत बन जाती हैं। मनरेगा योजना में अनियमितता के सैकड़ों मामले सामने आ चुके जिनसे प्रमाणित हुआ कि निगरानी तंत्र न होने से योजना का धन मनमाने तरीके से अपात्रों को बांटा गया। इससे उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा जो वास्तव में पात्र थे। नई सरकार ने समाज कल्याण, समरसता और समन्वय के प्रति प्रतिबद्धता का वायदा किया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मानवाधिकार हनन रोकना उसकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। पिछली सरकारों के दौरान हुई खामियों से सबक लेते हुए ऐसा आधार तैयार करे जो सभी को आश्वस्त करने में सक्षम हो। सवाल सरकार की साख और विश्वसनीयता का भी है। उसे सुनिश्चित करना होगा कि दलित उत्पीड़न किसी कीमत पर न होने पाए, पुलिस की भूमिका रक्षक और सहयोगी की रहे और भ्रष्टाचारियों पर दिखावे का नहीं, हकीकत में अंकुश लगे।

विदेशों से ज्यादा देश में इकट्ठा किए गए काले धन के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं संजय गुप्त

काले धन का कारोबार

संसद में चर्चा के साथ ही देश का ध्यान एक बार फिर काले धन की समस्या की ओर गया है। काले धन के मसले पर संसद में तृणमूल कांग्रेस के हंगामे को एक राजनीतिक नाटक ही माना जाएगा, फिर भी यह एक यथार्थ है कि काला धन एक बड़ी समस्या बन गया है और केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इससे किसी न किसी रूप में जूझ रही है। भारत में काले धन पर लोगों की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि काली कमाई के मामले में कई देश भारत से भी आगे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की एक रपट के अनुसार काले धन का सृजन करने वाले 150 देशों की सूची में भारत आठवें स्थान पर है। इस संस्था के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले में चीन, फिलीपींस, मैक्सिको समेत सात देश भारत से भी आगे हैं। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के कारण ही पूरी दुनिया में सरकारें सामाजिक कार्यों के लिए पैसे के अभाव से जूझ रही हैं। उनकी इस साझा समस्या को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वे बिना किसी देरी के ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचें जिससे न केवल काले धन के कारोबार पर अंकुश लगे, बल्कि कर चोरी कर इकट्ठा किए गए धन को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाया जा सके। पिछले दिनों ब्रिस्बेन में जी-20 सम्मेलन में काले धन के खिलाफ विश्व समुदाय के बीच बेहतर तालमेल और पारदर्शिता के भारत के सुझाव को पूरा समर्थन मिला, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। दुनिया के प्रमुख देशों को इस सहमति के अनुरूप ठोस कदम भी उठाने होंगे। उन्हें कर चोरी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करना होगा और उन देशों के खिलाफ एकजुट होना होगा जो काले धन के स्वर्ग बन गए हैं।

भारत में काले धन पर वर्षों से बहस हो रही है, लेकिन एक के बाद एक सरकारें इस आधार पर अपनी निष्क्रियता को उचित ठहराती रहीं कि कानूनी रूप से उनके हाथ बंधे हैं। वे संभवतः इस इंतजार में हैं कि कब अंतरराष्ट्रीय कानून बदलें और उनके हाथ काले धन वाले लोगों तक पहुंच सकें। तीन-चार वर्ष पूर्व जब विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तब लगभग हर देश को इसका अहसास हुआ था कि उनके यहां के लोगों का जो काला धन स्विट्जरलैंड सरीखे टैक्स चोरी के ठिकानों में जमा है उसे वापस लाया जाना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने घरेलू कानून के आधार पर काला धन जमा करने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं करते। अमेरिका को ऐसे देशों पर अंकुश लगाने में आंशिक सफलता मिली, जिसके आधार पर उसने अपने देश के कर चोरों के नाम जान लिए। इसके बाद दबाव में आए कुछ देशों ने अपने घरेलू कानून बदले भी हैं और कर चोरी से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कर चोरी के स्वर्ग माने जाने वाले देशों को पारदर्शिता के लिए मजबूर किए जाने में पूरी तरह सफलता मिल गई है।

स्विट्जरलैंड उन देशों में प्रमुख है जहां भारतीयों का अच्छा-खासा काला धन जमा है। वहां के एक बैंक एचएसबीसी से लीक हुई एक सूची से उन भारतीयों के नाम पता चल गए जिनके उस बैंक में खाते हैं और जिसके बारे में अनुमान है कि उनमें काला धन जमा है। मात्र एक बैंक से मिली सूची से ही भारत समेत कई देशों में खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी काले धन के मामले में सख्त रवैया अपनाया और उसने इसकी जांच-पड़ताल के लिए विशेष जांच दल बनाने का निर्देश दिया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने हरसंभव तरीके से यह कोशिश की कि ऐसे किसी जांच दल का गठन न हो। पिछले आम चुनाव में भी काला धन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में काले धन को लेकर कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों को लगातार कठघरे में रखा। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनने के बाद न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष जांच दल का गठन किया गया, बल्कि पिछली सरकार की तुलना में अधिक सक्रियता से काले धन पर अंकुश लगाने की पहल भी की गई। वित्त मंत्रालय इसके लिए प्रयासरत है कि मौजूदा कानून के तहत ही विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विदेशों में भारतीयों का अच्छा-खासा धन जमा है और इसमें एक बड़ा भाग ऐसे धन का है जो टैक्स की चोरी कर अथवा अवैध तरीके से अर्जित किया गया है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इसकी तुलना में देश के भीतर कहीं अधिक काला धन है। राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों और नौकरशाहों ने बड़े पैमाने पर अवैध कमाई का धन देश के भीतर इकट्ठा कर रखा है। इसकी एक ताजा बानगी नोएडा के एक इंजीनियर के यहां आयकर विभाग के छापे में सामने आई करोड़ों की काली कमाई है। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। उच्च पदों पर तैनात रहे दर्जनों अधिकारियों के घरों और दूसरे ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर काला धन जमा करने के प्रमाण सामने आ चुके हैं। जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो कुछ दिन तो शोर-शराबा मचता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। इससे आम जनता के बीच यह धारणा कर रही है कि हर सरकारी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार और कर चोरी के मामले में जो हाल प्रशासनिक तंत्र का है वही उद्योगपतियों और निजी क्षेत्र में उच्च पदों पर काम करने वाले लोगों का भी है। वे गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने के साथ कर की चोरी भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर भी यह स्वीकार किया गया है कि देश में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में जमकर काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। काले धन के कारण ही जमीन-जायदाद की कीमतों में भारी उछाल बना रहता है और वे आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विस्फोटक हो सकती है। विदेश से काला धन वापस लाने अथवा दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में कुछ विदेशी समझौतों के कारण सरकार के हाथ बंधे हो सकते हैं और उनका जिक्र विगत दिवस किया भी गया, लेकिन देश के भीतर काले धन के कारोबार पर अंकुश लगाने में क्या अड़चन है, इसका जवाब सामने आना शेष है।

अपने देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा ठिकाना राजनीति है। कभी समाजसेवा का माध्यम मानी जाने वाली राजनीति आज पैसा बटोरने का जरिया बन गई है। छात्र संघों से लेकर संसदीय चुनावों तक की राजनीति पैसों पर टिकी है। जिस देश में विधानसभा का चुनाव लड़ने में भी करोड़ों रुपये की जरूरत होती हो वहां की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की कल्पना की जा सकती है। राजनीतिक दल खुद को मिलने वाले चंदे की सही-सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। वे ऐसे कोई नियम-कानून बनाने में भी रुचि नहीं रखते जिनसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। इस मामले में हर दल कठघरे में है। अगर मौजूदा सरकार वाकई देश को यह संदेश देना चाहती है कि वह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे सबसे पहले राजनीति में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना होगा।

response@jagran.com

स्वाभाविक सवाल

◆ विदेश से काला धन वापस लाने में सरकार के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन देश के भीतर काले धन के कारोबार पर अंकुश लगाने में क्या अड़चन है, इसका जवाब सामने आना शेष है

नए मोड़ पर जम्मू-कश्मीर

चुनाव से गुजर रहे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हालात और भावी दिशा पर निगाह डाल रहे हैं **स्वप्न दासगुप्ता**

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुआ उत्साहजनक 71 फीसद मतदान और अब तक चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर शांतिपूर्ण रहना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सरकार के खिलाफ बने माहौल का परिणाम है या नहीं, इसका पता तब चलेगा जब आगामी 23 दिसंबर को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। ओपिनियन और एक्जिट पोल के अभाव में विश्लेषक मीडिया रिपोर्ट पर निर्भर होते हैं। फिलहाल निष्कर्ष तीन वृहद घटनाक्रमों की ओर संकेत करते हैं। पहली बात यह हो सकती है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और कहीं अधिक शक्तिशाली मानी जाने वाली उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को कश्मीर घाटी की 46 सीटों पर सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस और उसकी सहयोगी कांग्रेस घाटी में जबर्दस्त हार की ओर बढ़ रही हों। इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि भाजपा के उभार और जम्मू क्षेत्र से किसी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना के डर से वे तमाम लोग प्रेरित-उत्साहित हुए हों जो भले ही हुर्रियत कांफ्रेंस जैसी पार्टियों से कम सक्रिय रूप में जुड़े हैं। इस क्रम में अंतिम बात यह भी हो सकती है कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में तगड़ी पहुंच बना ली है।

जम्मू में भाजपा की बढ़त कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की कीमत पर है। इसके अतिरिक्त भाजपा ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और कश्मीर घाटी की कम से कम छह सीटों पर उसकी पकड़ बन गई है। 87 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों के स्थानीय बंटवारे के मुताबिक भाजपा द्वारा खुद के लिए निर्धारित 44 से अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि जम्मू और लद्दाख क्षेत्र की सभी सीटें भाजपा के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। भाजपा के चुनावी प्रदर्शन की बात छोड़ भी दें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नए आयाम जोड़ने का काम किया है। कश्मीर घाटी में दिल्ली से गए एक रिपोर्टर ने मुझे एक आश्चर्यजनक बात बताई कि भाजपा उम्मीदवार स्वयं मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले यदि वह ऐसा करते तो उन्हें खतरा होता। कुछ का मानना है कि जब वहां भयावह बाढ़ आई थी तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण लोगों के बीच उनके प्रति वैर-विरोध कम हुआ है तो कुछ का मानना है कि भारत के अन्य भागों की तरह ही यहां भी लोग प्रधानमंत्री को एक मौका देना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो और सबको लाभ मिले। मुझे एक रोचक बात देखने को मिली कि खुद महबूबा मुफ्ती अपने चुनाव अभियानों में स्मार्ट सिटी के महत्व को बता रही हैं, जबकि कुशासन के लिए नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस सरकार को कोस रही हैं।

यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा और अनुच्छेद 370 का मुद्दा पूरी तरह चुनावी परिदृश्य से गायब है। दिल्ली आधारित मीडिया भी इस बारे में अपने काल्पनिक खतरे को उठाता ही रहता है, बावजूद इसके जो बात अधिक रोचक है वह यही कि यह जानते हुए भी कि भाजपा जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में पूर्ण रूप से मिलाए जाने के पक्ष में है, इस्लामिक पहचान के मुद्दे को हवा नहीं मिल पा रही है। लंबे समय से जम्मू-कश्मीर राजनीतिक खींचतान का शिकार रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए काल्पनिक एजेंडे भी पेश किए जाते रहे हैं। इनमें से कुछ तो समस्या को महज पाकिस्तानी नजरिये से देखती हैं। उनकी धारणा-जिज्ञासा आतंकवाद केंद्रित न होकर इस राष्ट्रीय समस्या के बहुराष्ट्रीय समाधान पर केंद्रित है। कुछ लोगों की धारणा है कि यदि मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर शासन अधिक संवेदनशीलता बरते तो चमत्कारी बदलाव संभव है। ऐसा भी नहीं है कि उनकी सभी आपत्तियां और विरोध गलत हैं। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। पहली बात यही है कि कश्मीर घाटी न तो अल्पविकसित है और न ही भारतीय मानकों के लिहाज से यह गरीब है। इसके उलट सच्चाई यही है कि अपेक्षाकृत रूप से जम्मू क्षेत्र कहीं अधिक उपेक्षित है। जम्मू क्षेत्र में धारणा यही है कि विकास के लिए उनके पास संसाधनों की कमी इसलिए है, क्योंकि दिल्ली के प्रति अनवरत समर्थन के कारण उन्हें बहुत महत्व नहीं मिल पाता। यह भी महत्वपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ से सर्वाधिक मदद पाने वाले राज्यों में शामिल है। हालांकि यह राज्य आंतरिक तौर पर कोई बहुत राजस्व नहीं पैदा करता। इसके नागरिकों पर कर नाममात्र का है, जबकि सब्सिडी के रूप में उन्हें बहुत अधिक मदद मिलती है। सीमावर्ती राज्य के तौर पर इस विशिष्ट दर्जे का उल्लेख वित्त आयोग भी करता है। इस राज्य के नागरिकों को टैक्स दरों के मामले में अचानक से किसी भारी वृद्धि से भी डरने अथवा विकास के लिए मिली निधि के वापस होने की आशंका नहीं है। जरूरत इसकी है कि केंद्र और राज्य सरकार खर्च की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें। लंबे समय से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में राष्ट्रीय एकीकरण को विकृत व्यवहारवाद के आधार पर देखा गया। इन नीतियों का प्रभाव यह हुआ कि स्थानीय संपन्न वर्ग को भ्रष्टाचार का मौका मिला। इस तरह के अनैतिक शासन का प्रभाव बहुत खतरनाक साबित हुआ। वर्तमान चुनाव में इस बात को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। भाजपा की उपस्थिति और किसी बड़े बहिष्कार अभियान की अनुपस्थिति के कारण यह अंतर आया है। नई सरकार के पास धारणा को बदलने और नई राह पर चलने का मौका है। फिर भी अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता रहेगी ही।

मेरे विचार से पुलिस के कार्यों से जुड़ी चीजों से सेना की चरणबद्ध वापसी और भलीभांति प्रशिक्षित और संवेदनशील केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती महत्वपूर्ण हो सकती है। केवल नियंत्रण रेखा पर ही भारतीय सेना की सक्रिय तैनाती हो। अलगाववादियों-विद्रोहियों का प्रतिरोध राज्य के हाथों में होना चाहिए। चुनाव परिणामों के बाद श्रीनगर और दिल्ली समेत जम्मू-कश्मीर के प्रति धारणा में कुछ बदलावों की आवश्यकता होगी।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नया आयाम

◆ भाजपा के चुनावी प्रदर्शन की बात छोड़ भी दें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नए आयाम जोड़ने का काम किया है

ऊर्जा

विरोधाभास

प्रायः हमें अपने जीवन में सुख के साथ दुख, जन्म के साथ मृत्यु, प्रेम के साथ घृणा जैसी विलोमार्थी घटनाएं अनिवार्य रूप से घटित होती दृष्टिगत होती हैं। यही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति ही एक विचित्र से विरोधाभास पर टिकी नजर आती है। जन्म के साथ मृत्यु, सुख के साथ दुख, जिसे हम प्रेम करते हैं, देर सवेर उसके प्रति घृणा का भाव हमारे मन में उठता है तो हम विस्मित भी होते हैं और व्यथित भी। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें जीवन में प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थानों पर विरोधाभासी तथ्य क्यों नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तथ्य प्रत्यक्ष में ही विरोधाभासी नजर आते हैं और गहन रूप से ये एक दूसरे के सहायक यानी परिपूरक हों।

निश्चित रूप ये ऐसा ही है। उदाहरण के लिए मृत्यु न हो, तो नए बच्चों के जन्म का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। हम जमीन पर चलते हैं, तो हमारे पांवों में विरोधाभास होता है। अर्थात हमारा एक पैर जमीन पर और दूसरा अधर में होता है। अगर हम इस विरोधाभास को नकारते हुए ये कहें कि हम या तो दोनों पैर धरती पर रखेंगे या हवा में उठाएंगे, तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम कल्पना कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन को गतिमान यही विरोधाभास बनाते हैं। वास्तव में ये पूरी प्रकृति ही सतत परिवर्तन व विनाश के मूलाधार पर टिकी हुई है और एक वर्तुल में घूमती है। नजर आने वाले ये विरोधाभास ही एक वर्तुल को गति देते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक रात्रि (दुख) इस सत्य की उद्घोषणा है कि सुबह (सुख) दूर नहीं। सभी चीजें परस्पर बदलाव के क्रम में हैं। एक कार्य का खत्म होना दूसरे कार्य की शुरुआत है। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु वास्तव में उसके नवजीवन की आधारशिला रख रही होती है। इसलिए हमें इन विरोधाभासों को खुले मन से स्वीकार करते हुए ये समझना होगा कि इससे ही हमें नित-नए संघर्ष करने की झलक मिलती है और भट्टी से निकले सोने की तरह हमारा जीवन निखरता है। इन विरोधाभासों को समझते ही हमारे जीवन में संतुलन और मध्य मार्ग खुल जाता है। इस मध्य मार्ग को भगवान बुद्ध ने भी मान्यता दी है। संतुलित जीवन ही सुख व शांति का आधार है। याद रखें, इस संसार में शांति से बढ़कर कोई अहसास नहीं है।

◆ **अजय गोंडवी**

जागरण Junction — AAPKI AWAAZ, AAPKA BLOG — www.jagranjunction.com

गठजोड़ का अंधाधुंध प्रयास

जनता दल परिवार के एकसाथ बैठने के बाद कांग्रेस ने भी नेहरू की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजन कराने के बहाने सेक्युलर विपक्ष का गठजोड़ बनाने की पहल की है। वामपंथी दल भी जनता दल परिवार की एकजुटता को सकारात्मक बता रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों के गठजोड़ की वकालत की है। लोकसभा के चुनाव के बाद बने राजनीतिक परिदृश्य में मोदी की एकछत्र हुकूमत कायम होती जा रही है। मोदी के पीछे संघ की विचारधारा है और एक मजबूत वैचारिक एजेंडे पर काम करने वाली राजनीतिक शक्तियां निरंकुश शासन चाहती हैं। भले ही वे शक्तियां दक्षिणपंथी हों या वामपंथी। यही वजह है कि मोदी ने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के तकाजे पर कोई ध्यान न देते हुए निर्धारित संख्या की तकनीकी आड़ में कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा देना कबूल नहीं किया। ऐसा लगता है कि लोगों में अभी लोकतांत्रिक संस्कारों की पैठ बनने में समय लगेगा। भारत के लोग आज भी निरंकुश नेतृत्व के प्रति आकर्षित रहते हैं। **केपी सिंह**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1v3zd6C

क्रिकेट से खिलवाड़

क्रिकेट फिर कठघरे में है। आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में उच्चतम न्यायालय ने श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन की भूमिका किसी भेदिया जैसी बताई है। इसके अलावा मुद्गल समिति की रिपोर्ट में नामजद खिलाड़ियों के नाम उजागर करने की अपील पर भी सुनवाई की मंजूरी दे दी है। देखना है पिटारे से क्या निकलता है। कुछ निकलता भी है कि नहीं। लेकिन इतना तय है कि जो भी हो रहा है वह इस खेल के हित में तो कतई नहीं है। देखा जाए तो क्रिकेट में पैसे और ग्लैमर के बढ़ते प्रभाव ने इस खेल की नींव को खोखला करना शुरू कर दिया है। आइपीएल ने इस खेल के स्वरूप को भी बहुत हद तक बदला है। इसने खिलाड़ियों की सोच में देश भावना को नहीं, बल्कि पैसे की भावना को जागृत करने का काम किया है। **एलएस बिष्ट**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1CrwbhB

बहुभाषी स्मृति

संस्कृत और जर्मन विवाद में स्मृति इरानी भले ही इन दिनों फंसी हों। मगर मानव संसाधन विकास मंत्री की बहुभाषी क्षमता के मुरीद तमाम सांसद हो गए हैं। बंगाली सांसदों से बंगाली भाषा में तो मराठी सांसदों से मराठी में वह बेझिझक बात करती हैं। इतना ही नहीं, एआइडीएमके सांसद से जब वह मिलीं तो भी उन्होंने तमिल भाषा का अधिकाधिक इस्तेमाल किया। हालांकि, तमिलनाडु के सांसद अंग्रेजी में बेहद सहज और पारंगत होते हैं। बहरहाल, स्मृति की इस बहुभाषी क्षमता के जहां लोग कायल थे, वहीं कांग्रेस सांसद चुटकी लेने से भी नहीं चूके। एक पूर्व मंत्री ने तो कहा कि स्मृति को अब जर्मन भी सीख लेनी चाहिए ताकि वह जर्मन राजदूत से भी उनकी भाषा में बात कर संस्कृत विवाद मामले पर से उपजी कड़वाहट को दूर कर सकें।

करीबी पड़ रही महंगी

राजग सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिन्हें पहली बार में काफी अहम जिम्मेदारियां दी गई-ऐसे कि कई लोगों ने भौंवे उचका कर अचरज जताया। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके नेतागीरी कॅरियर की शुरुआत ही बीते आम चुनाव से हुई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह महीने बाद अपनी टीम में विस्तार के बहाने जो बदलाव किए उनमें से कई के कद में कतर-ब्यौंत भी हुई। इसमें ऐसे ही एक मंत्री महोदय भी शामिल हैं जिनका सियासी कद कुछ छोटा भी हुआ। माना जा रहा है कि इसमे पीछे एक वजह उनके एक करीबी सहयोगी के क्रियाकलापों पर उठे सवाल और जांच की उंगलियां भी शामिल हैं। यह बात और है कि मंत्रीजी के आधिकारिक निजी सचिव भले ही अब तक कई बदल चुके हैं, लेकिन सवालों के घेरे में आए सहयोगी की नजदीकी और दखल बरकरार है। यह बात और है कि मंत्री साहब सियासत में आने से पहले और बाद में भी अपनी साफ छवि का काफी बखान करते रहे।

दूरदर्शन ने फिर कटाई नाक

केंद्र सरकार हर साल गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस आयोजन को लेकर मंत्रालय से ही संबद्ध सरकारी चैनल दूरदर्शन भी खूब सक्रिय रहता है। इसने अपने न्यूज चैनल ही नहीं, मुख्य चैनल (डीडी राष्ट्रीय) पर भी वहां से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की। मगर कांट्रेक्ट पर रखी गई जिस एंकर को यह जिम्मेदारी दी गई उसने इतना हास्यास्पद काम किया कि अब अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा। यहां तक कि उसने गोवा की राज्यपाल को भारत का गवर्नर बताया। अब प्रसार भारती ने पूरे मामले पर सफाई मांगी है। अगर इसने यह जिम्मेदारी अपने न्यूज चैनल के लोगों को भी दी होती तो भी इतनी भद तो नहीं पिटती। खास बात यह है कि इस मामले पर दूरदर्शन के अधिकारी तब जगे, जब सोशल मीडिया पर इसकी रिकार्डिंग साझा की जाने लगी।

सेहत ताक पर

प्रधानमंत्री मोदी भले ही अपने मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचने की नसीहत बार बार देते रहे, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा। खास तौर पर राज्य मंत्रियों का प्रदर्शन तो शीतकालीन सत्र में अभी तक बहुत ही खराब रहा है। लोक सभा में पिछले हफ्ते प्रश्न काल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री के साथ कुछ अन्य मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों के जवाब से इनकी तैयारियों का खुलासा हो गया। एक मानव संसाधन राज्य मंत्री के समक्ष जो भी सवाल आता था उसका उन्होंने बस एक रटा रटाया जवाब दिया, 'आपकी चिंता जायज है और सरकार इस पर कदम उठाएगी।' हद तो तब हो गई जब सवाल पूरे देश के बारे में किया गया था, लेकिन जवाब वह अपने गृहराज्य के संदर्भ में देने लगे। संसद सदस्यों की तरफ से उन्हें बार-बार याद दिलाने के बावजूद मंत्री महोदय अपने गृह राज्य की सीमा से बाहर निकल नहीं सके।

ज्योतिषियों के नक्षत्र

केंद्रीय मंत्री के ज्योतिषी को हाथ दिखाने के बाद उपजे विवाद से तमाम राजज्योतिषियों के नक्षत्र भी आगे-पीछे हो गए हैं। एक-एक कदम ज्योतिषियों से पूछकर बढ़ाने वाले मंत्रीवर फिलहाल थोड़ा चौकन्ने हो गए हैं। घरों में ज्योतिषियों की आमद कम करा दी गई है। हालांकि, इसका असर केंद्र में नए-नए मंत्री बने भाजपा के पूर्व महासचिव पर बिल्कुल नहीं है। पहाड़ से मैदान आने की भविष्यवाणी के बाद केंद्र सरकार में नए बने मंत्रीजी बिना ज्योतिषी की सलाह पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। रोजाना फाइलों पर दस्तखत करने के समय से लेकर घर से निकलने तक के मामले में ज्योतिषियों के परामर्श का पूरा पालन हो रहा है।

ट्वीट ट्वीट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें चार साल के न्यूनतम स्तर पर हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। मोदी ने संप्रग के कार्यकाल की अप्रैल-जून की 5.7 प्रतिशत जीडीपी का श्रेय लूट लिया। अब मोदी सरकार में यह गिरकर 5.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

संजय झा @JhaSanjay

कांग्रेस ने राहुल गांधी से मोदी के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और उनका विरोध करने के लिए कहा। अपनी ही शैली में राहुल ने मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का विरोध करने का फैसला किया।

इंडिया स्पीक्स @IndiaSpeaksPR

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप गावस्कर के इस विचार से सहमत हैं कि फिल ह्यूज की मौत के कारण भारत-आस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच आगे खिसकाया जाना चाहिए?

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव तक मुख्य मुकाबले में आ जाएगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें

Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।